



Economy

Explanation

18 May, 06:30 pm (TEST : 08)

1. (d) दिए गए सभी कथन सत्य हैं। अतः अभीष्ट उत्तर (d) होगा।
व्याख्या : पूँजीगत अनुदान (Capital Grants) संपत्ति निर्माण की शर्त पर केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान है। राजस्व घाटा ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों हो सकता है। यदि सरकारी बजट के खाते की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो राजस्व घाटा कहलाता है।
2. (c) उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। अतः अभीष्ट उत्तर (c) होगा।
3. (d) **व्याख्या-**
राजस्व घाटा : यदि सरकारी बजट के राजस्व खाते की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो घाटे की मात्रा राजस्व घाटा कहलाती है।
बजट घाटा : राजस्व घाटा तथा पूँजीगत घाटे का योग ही बजट घाटा कहलाता है।
राजकोषीय घाटा : यह एक समग्र घाटा है, जो वास्तव में सरकार की समग्र बजेटरी आय तथा समग्र बजेटरी व्यवहार से उत्पन्न कुल देयताओं से प्रदर्शित होती है। यहां हम आय से संबंधित बात कर सकते हैं, प्राप्तियों की नहीं।
प्राथमिक घाटा : राजकोषीय घाटे में से सरकारी बजट के कुल ब्याज भुगतान को घटाने पर जो शेष बचता है, उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं।
4. (b) कथन 1 और 2 सत्य हैं, जबकि कथन 3 असत्य है। अतः अभीष्ट उत्तर (b) होगा।
5. (c) उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। अतः अभीष्ट उत्तर (c) होगा।
व्याख्या : 1997 से पहले भारत में बजट घाटे की अवधारणा का प्रयोग किया जाता था। इससे सरकार की राजकोषीय स्थिति का ठीक से पता नहीं लग पाता था। प्रायः बजट घाटे को मौद्रिक घाटा भी कहते हैं, इसका कारण यह है कि इस घाटे के मूल्य के बराबर की मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है। 1997 से पहले भारत में बजट घाटे की अवधारणा का प्रयोग किया जाता था।
6. (c) उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। अतः अभीष्ट उत्तर (c) होगा।
व्याख्या : बजट घाटे के वितरण की दो विधियाँ हैं। जिसमें सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के पास बढ़े हुए नकद शेषों को कम करना तथा सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से उधार लेना है। उपर्युक्त दोनों मामलों में मुद्रा की मात्रा पहले की तुलना में अधिक हो जाती है।
7. (c) पूँजीघाटा
8. (d) उपर्युक्त दोनों कथन असत्य हैं। अतः अभीष्ट उत्तर (d) होगा।
व्याख्या : भारत जैसे राष्ट्रों में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इस बात को सुझाव दिया जाता था कि आर्थिक विकास के लिए हीनार्थ प्रबंधन की रणनीति को लागू किया जाता है। भारत में 1997 से बजट घाटे को शून्य पर रखने की नीति को ध्यान में रखा जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में भारत में सरकारी घाटे मुद्रा का रूप नहीं लेते हैं।
9. (c) कथन 2 और 3 सत्य हैं, लेकिन कथन 1 असत्य है। अतः अभीष्ट उत्तर (c) होगा।
व्याख्या : FRBM (Fiscal Responsibility & Budget Management) को 2003 में लाया गया था तथा 2004 में लागू किया गया था। FRBM एक्ट एन.के. सिंह समिति से संबंधित है।
10. (d) उपर्युक्त दोनों कथन असत्य हैं। अतः अभीष्ट उत्तर (d) होगा।
व्याख्या : 2019-20 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% स्तर पर लाया जाना चाहिए तथा 2022-23 तक राजस्व स्तर के घाटे को जीडीपी के 8% तक किया जाना चाहिए।

* * *

ANSWER KEY

Economy (00 May, 2018) Test No. 08

1.	(d)	2.	(c)	3.	(d)	4.	(b)	5.	(c)	6.	(c)	7.	(c)	8.	(d)	9.	(c)	10.	(d)
----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----